सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम 76 रुपये क्विंटल पर किसानों से गेहूं खरीदेंगे, लेकिन मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बारे में निजी जानकारी है, आज 4 मई तक अनेकों केन्द्रों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किये गये हैं, कोई सरकारी कर्मचारी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंचे और जिन केन्द्रों में कुछ कर्मचारी पहुंचे, वे भी किसानों के लिये अनेकों कठिनाई और परेशानी पैदा किये हुये हैं। मैंने स्वयं मौके पर जा कर देखा है, पहले गेहूं आढ़ती के पास जायेगा, उसके बाद आढ़ती का माल ज्यादा खरीदते हैं, किसानों का ज्यादा नहीं खरीदते हैं। जहां थोड़ी बहुत खरीद है, वहां भी लाइन में लगने के सम्बन्ध में, चैक देने के सम्बन्ध में कई कई दिन तक चैक के न भुनने के सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें आ रही हैं। तोल के सम्बन्ध में भी शिकायत है कि सही तोल नहीं की जा रही है, इस तरह से किसानों के अन्दर बहुत ज्यादा असन्तोष फैल रहा है।

मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो घोषित नीति है, उस पर अमल कराये। अब तक उसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि किसान को अपना सारा गल्ला, विशेष कर जो छोटे किसान हैं जो गल्ले को जमा कर के नहीं रख सकते, आढ़तियों के यहां ले जाना पड़ता है, क्योंकि केन्द्रों में अभी तक सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं।

इस बार इस काम के लिए तीन ऐजन्सियों की घोषणा की गई थी—खाद्य निगम खरीदेगा, कोआपरेटिव विभाग खरीदेगा और स्टेट गवर्नमेंट्स खरीदेंगी, इन तीन एजेन्सियों के बावजूद भी अभी तक उनके खरीददार केन्द्रों में नहीं पहुंचे हैं और जहां पहुंचे हैं वहां भी से शिकायतें आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि कृषि मन्त्री तुरन्त अपनी घोषित नीति पर अमल करें और किसानों से जो वायदा किया है गल्ला खरीदने का, उसको वह पूरा करें।

MR SPEAKER : I allowed these three hon Members because their motion is pending with me The calling Attention scheduled for today had to be postponed because the Minister was not there. So, I am allowing them one or two minutes each to express their viewpoint

(II) CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) अध्यक्ष महोदय, जमीन की सीलिंग के सवाल को लेकर जिस प्रकार का वाद-विवाद आज अखबारों में और देश में सब जगहों पर उठ खड़ा हुआ है उसके बारे में सरकार की जो नीति है

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : वह खाद्य मंत्रालय को गुमराह करने वाली नहीं है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है।

श्री नाथराम मिर्धा : आपकी राय में है। खाद्य मंत्रालय की कुछ जिम्मेदारी है।

श्री बी० पी० मौर्य : कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिम्मेदारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का वाद-विवाद बहुत दिनों तक चलते देना अच्छा नहीं है। इस सारे मामले पर एक दफा गहराई से सोचना चाहिए—क्या हमारी नीति है, क्या हम चाहते हैं, क्या हमारा समाजवाद है, क्या एक परिवार की आमदनी की तस्वीर देश में होनी चाहिए—ये सारे अहम सवाल हैं और कई दूसरे मामलों के साथ जुड़े हुए हैं। इस लिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा समय निकाला जाय, जिसके जरिये इस सदन में बैठने वाले हम सब लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान अच्छी तरह से कर सकें इस सारे मामले पर गहराई से सोच सकें। हम इस देश में लोकतन्त्र चाहते हैं, लोकतन्त्र के जरिये इस देश में जो गरीबी व्याप्त है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं देश के धन को बढ़ाना चाहते हैं और उस का सही वितरण करना चाहते हैं, उसके लिए तमाम

[श्री नाथूराम मिर्धा]

सिद्धान्तों, नीतियों और देश के हालत को सामने रखकर चलना होगा। आज प्रगतिशीलता की कुछ होड़-सी लगी हुई है, बहुत से लोग समझते है कि 10 एकड की सीलिंग होनी चाहिए, दूसरे कहते है कि पांच एकड की होनी चाहिए, तीसरे कहते है कि दो एकड़ की होनी चाहिए। क्या सीलिंग हो और क्या न हो, इस देश मे परिवार की क्या तस्वीर हो, इस सदन मे वे सारे विचार सामने आ जायें, क्योंकि कुछ लोग इण्डिविजुअल प्रापर्टी और लोकतन्त्र मे विश्वास करते हैं और उनकी होड़ कुछ दूसरे लोगों से लगी हुई है। इस देश मे समाजवाद का क्या नकशा बनाना चाहते है, यह बड़ा अहम सवाल है और इसके बारे में गहराई से सदन मे विचार होना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार के सामने इस बात को रखें और समय तय किया जाये ताकि हम बैठकर जिम्मेदारी से उस पर विचार कर सकें, ताकि लोगों के अन्दर जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, वह दूर हो सके। आज 75 फीसदी लोग जमीन के सवाल से जुड़े हुए हैं, उनके अन्दर अनिश्चितता पैदा हो रही है, सारे देश के अन्दर एक हलचल सी मची हुई है, इसलिए इस पर गहराई से सोचने का मौका प्रदान करें।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : Mr. Speaker, Sir, while endorsing the sentiments expressed by my friends, I may say that the introduction of land reforms and ceilings have to be done in pursuance of the promise given to the people by the party in power. So, land reforms and ceilings should not brooke any delay. The State Governments are also engaged in this matter. But, unfortunately, instead of giving a clear and correct perspective of the socio-economic changes that are being brought about by land ceilings, a controversial twist is being given to the recommendations of the Central Land Reforms Committee and the statement made by the Minister for Agriculture on the floor of the House.

SHRI B. P. MAURYA : That statement is most confusing.

SHRI P. VENKATASNBBAIAH : The centire agcicultural community and also a vast section of our population who depend on agricultural operations in this country are very much perturbed and they are not sure of what is going to happen in the light of this unnecessary and unseemly controversy that is being carried on. So it is necessary that this supreme body, the soverign representative of the people of this country...

SHRI PILOO MODY (Godhra) : That is No. 1, Safdarjung Road.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : ...should have a correct perspective of this matter and have a full dressed debate so that the land reforms are implemented effectively for the benefit of the vast mass of people who depend on agriculture.

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के सवाल को लेकर जो हमारे खेतिहर लोग हैं, उन सब मे एक तरह की चिन्ता, एक तरह की अपहीवल पैदा हो गई है। हम सीलिंग चाहते है लेकिन सीलिंग किस तरह से हो, यह सब मुल्क के सामने आना चाहिए और एक मर्तबा तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कोई समय निश्चित कर दीजिए, कम से कम एक दिन का समय हो, जिससे इस पर फुल डिबेट हो जाय और हर प्वाइन्ट आफ व्यू हाऊस के सामने आ जाय।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I want to draw attention to the statement made by the Minister...

MR. SPEAKER : Only those hon. Members who have given notice and their names are entitled to speak.

SHRI SAMAR GUHA : Sir, on a point of order. When the Minister made a statement on land ceilings and we demanded that there should be a full-dressed debate, you observed that if that is the desire of the House it can be taken into consideration. On the basis of that, many hon. Members have sent their notices.

MR. SPEAKER This is only a submission ; not a point of order.

SHRI SAMAR GUHA : So, how can you allow only a few chosen members ; I would rather say a few members, and not 'chosen' members ?

MR SPEAKER You are also chosen sometimes. As you are chosen They have given notice of it. There was no Calling Attention notice today and they gave notice of it this morning and I allowed them.

SHRI K SURYANARAYANA (Eluru) Sir, I would request you to give us an opportunity discuss all the statements that have been laid on the Table of the House regarding land reforms Not only the policy of land reforms but every income of an individual or an institution should be discussed. That is my contention. Only last week, the hon Minister made a statement As Shri Samar Guha also said, that statement may also be discussed Though it is a State subject, the directions are being given by the Government of India also They have appointed the Central Land Reforms Committee They have not yet given any report So, I would request you to give us full opportunity, may be one or two days, if possible, to discuss it.

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सवाल है जिसमे हम देश मे जनतांत्रिक तरीके से शांतिमय क्रांति लाना चाहते है और एक नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इसमे छोटे किसानो का भी सवाल है और बडे किसानो का भी सवाल है इसलिये इस पर पूरी बहस होनी चाहिए।

MR. SPEAKER . If the Business Advisory Committee decides to allot some time for it, I have no objection.

12.22 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS, 1972-73—*Contd.*

MINISTRY OF STEEL AND MINES—*Contd*

MR. SPEAKER : We will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Steel and Mines. Shri Damodar Pandey was on his legs He may continue now.

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं जैसा कह रहा था कि भविष्य के लिये इस सम्बन्ध मे हमारी पालिसी स्पष्ट होनी चाहिए और उस दिशा मे ठोस कदम उठाने चाहिए। राष्ट्र की प्रगति के लिये जरूरी है कि उद्योग प्रगति करे और उद्योग का चक्का सारे देश मे चले। उस चक्के को चलाने के लिये शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति कोयले और दूसरी वस्तुओं से मिलती है जो कि चक्के को चलाती है। कोयले का सब्स्टीट्यूट निकालने का जो अभी तक प्रयास किया गया वह बहुत सफल नही हुआ और नये तरीके से फिर हम कोयले के ऊपर आये हैं। देश मे इसकी मात्रा बढी है और इसकी आवश्यकता भी बढी है। उस सन्दर्भ मे मैं कह रहा था कि अपने देश मे कोयले के जो भण्डार है उनके विकास के लिये नये सिरे से सबसे पहले यह जरूरी है कि खान की मिल्कियत समाप्त हो और पूरे कोल के भण्डार का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया जाये और नये सिरे से सोचे कि किस तरह से विकास करना है।

हमारे देश मे कोकिंग कोल की कमी है लेकिन नान-कोकिंग कोल के जो अक्षय भण्डार अपने यहा है उस भण्डार मे हम काफी आगे की दिशा मे सोचकर उपाय कर सकते है। अभी कोयले के उत्पादन की समस्या नही है। यदि कोयले के उत्पादन की समस्या होती तो उसे दूसरे ढग से सोचा जा सकता था। कोयले के उत्पादन के साथ साथ कोयले का ट्रान्सपोर्टेशन, कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी चीज है। अभी कोयले के उद्योग के विकास की दिशा में जब हम बात करते हैं तो यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसे कम से कम दूरी तय करनी पड़े ऐसी

*Moved with the recommendation of the President